सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा...

सरकारी धन लुटता रहा, अधिकारी जनसुविधा पर कैंची चलाते रहे

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . आमतौर पर सरकार पैसे की कमी बताकर जन सुविधाओं पर खर्च में कंजूसी करती है, लेकिन नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में उजागर हुआ कि विभाग यदि लापरवाही नहीं बरतते तो स्थिति उलट होती। विभागों ने राजस्व वसूली में लापरवाही बरती, परियजानाओं के क्रियान्वयन में लेटलतीफी के साथ ही सरकारी धन का दुरुपयोग किया।

राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी (आरयूएचएस) का अस्पताल 11 साल में भी पूरा नहीं हो सका। बारां में नर्सिंग स्कूल का भवन 9 साल में भी नहीं बना। बच्चों की मौत के कारण सुर्खियों में रहे कोटा मेडिकल कॉलेज ने यूआइटी के ठेकेदार पर 23 करोड़ की दरियादिली दिखा दी। जेंडर आधारित एक योजना में तो एक पैसा ही खर्च नहीं किया गया, परिवहन विभाग ने कई हजार वाहनों से कर ही नहीं लिया। सीएजी की शुक्रवार को विधानसभा में पेश चार रिपोर्टों से ऐसे ही कई खुलासे हुए हैं जिनसे जाहिर है कि योजनाएं बनत हैं लेकिन सरकारी धन के दुरुपयो से पूरी नहीं हो पाती हैं। समय प काम पूरा नहीं होने से खर्चा बोझ बनकर रह जाता है। 18329 करो रुपए बिना खर्चे रह गए,जो 31 मा को लौटाए गए।

(पेज 06 भी पढ़ें)

रियल एस्टेट पर रही मेहरबानी

आरएफसी एनपीए को लेकर सवालों में घिरी, 50% एनपीए राशि के लिए रियल एस्टेट की 8 फर्म जिम्मेदार मिलीं। गंगानगर शुगर मिल के संचालन में देरी से करीब 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।